

EXAM GENIUS
Presents
GENIUS
CURRENT
AFFAIRS

In Bilingual
07 Jan 2026



India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK | RAILWAY Exam

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques : As per RBI stress tests, what is the expected GNPA ratio of NBFCs under the baseline scenario by September 2026?

आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक आधारभूत परिदृश्य में NBFC का GNPA अनुपात कितना होने का अनुमान है?

- A) 2.3%
- B) 2.5%
- C) 2.7%
- D) 2.9%
- E) 3.5%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- Under the baseline scenario, RBI's stress tests project that the system-level Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of NBFCs will rise from 2.3% in September 2024 to 2.9% by September 2026.
- आधारभूत परिदृश्य के तहत, आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार NBFC का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात सितंबर 2024 के 2.3% से बढ़कर सितंबर 2026 तक 2.9% होने का अनुमान है।
- This indicates a gradual deterioration in asset quality, although overall capital adequacy (CRAR) is expected to remain well above the regulatory minimum of 15%.
- यह परिसंपत्ति गुणवत्ता में धीरे-धीरे गिरावट को दर्शाता है, हालांकि समग्र पूंजी पर्याप्तता (CRAR) नियामकीय न्यूनतम 15% से काफी ऊपर बनी रहने का अनुमान है।
- RBI also highlighted uneven resilience within the NBFC sector, with 8 NBFCs potentially falling below the minimum CRAR threshold even under the baseline scenario.
- आरबीआई ने NBFC क्षेत्र में असमान लचीलापन की ओर संकेत किया, जिसमें आधारभूत परिदृश्य में ही 8 NBFCs का CRAR न्यूनतम सीमा से नीचे जाने की संभावना है।





Ques: What key change has the Ministry of Corporate Affairs introduced regarding KYC compliance for company directors under the Companies Act, 2013?

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी निदेशकों के लिए KYC अनुपालन को लेकर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Mandatory monthly KYC filing / अनिवार्य मासिक KYC फाइलिंग
- B) Replacement of annual KYC with once-in-five-years filing / वार्षिक KYC को पाँच वर्ष में एक बार की फाइलिंग से बदलना
- C) Replacement of annual KYC with once-in-three-years simplified KYC / वार्षिक KYC को तीन वर्ष में एक बार सरल KYC से बदलना
- D) Complete removal of KYC requirement for directors / निदेशकों के लिए KYC आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना
- E) KYC filing applicable only to newly appointed directors / केवल नए नियुक्त निदेशकों पर KYC फाइलिंग लागू करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Corporate Affairs has eased compliance norms for company directors by replacing the mandatory annual KYC filing with a simplified KYC requirement once every three years.
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी निदेशकों के लिए अनिवार्य वार्षिक KYC फाइलिंग को हटाकर तीन वर्ष में एक बार सरल KYC की व्यवस्था लागू की है।
- This change follows a review of Rule 12A of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, based on the recommendations of the High-Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms and stakeholder suggestions.
- यह बदलाव कंपनियाँ (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12A की समीक्षा के बाद किया गया है, जो गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों और हितधारकों के सुझावों पर आधारित है।
- The amended rules were notified on December 31, 2025, and will come into effect from March 31, 2026.
- संशोधित नियमों को 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया और ये 31 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे।





- Under the revised framework, directors must submit a simplified KYC intimation once every three years instead of filing KYC annually.
- संशोधित ढांचे के तहत, निदेशकों को अब हर वर्ष के बजाय तीन वर्ष में एक बार सरल KYC सूचना देनी होगी।
- The revised KYC Form can be used for KYC compliance, updating mobile number, email address, residential address, and re-activation of Director Identification Number (DIN).
- संशोधित KYC फॉर्म का उपयोग KYC अनुपालन, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आवासीय पता अद्यतन करने तथा DIN के पुनः सक्रियण के लिए किया जा सकता है।
- Digital signature verification by the director and certification by a professional will be mandatory only when the KYC form is submitted for updating mobile number, email address, or residential address.
- डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन और किसी पेशेवर द्वारा प्रमाणन केवल तभी अनिवार्य होगा, जब KYC फॉर्म मोबाइल नंबर, ई-मेल या आवासीय पते के अद्यतन के लिए दाखिल किया जाए।
- Directors who have already completed their KYC requirements are covered under the new provisions, and their next KYC filing will be due by June 30, 2028.
- जिन निदेशकों ने अब तक अपना KYC पूरा कर लिया है, वे नए प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे और उनकी अगली KYC फाइलिंग 30 जून 2028 तक देय होगी।
- Directors who have not yet submitted their KYC Form can continue to get their DIN re-activated under existing provisions till March 31, 2026.
- जिन निदेशकों ने अब तक KYC फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च 2026 तक मौजूदा प्रावधानों के तहत अपना DIN पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to SEBI

- **The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has simplified the procedure for issuance of duplicate securities by increasing the monetary threshold for simplified documentation from ₹5 lakh to ₹10 lakh.**
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है।
- **The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has decided to exclude Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds and delisted securities from the valuation threshold used to determine eligibility for a Basic Services Demat Account (BSDA).**
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने BSDA की पात्रता तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन सीमा से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को बाहर करने का निर्णय लिया है।
- **SEBI has eased the re-KYC process for existing NRI clients by removing the requirement of being physically present in India during digital re-KYC.**
• SEBI ने मौजूदा NRI ग्राहकों के लिए डिजिटल re-KYC के दौरान भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता हटा दी है।
- **The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has approved Groww as an Online Bond Platform Provider (OBPP).**
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Groww को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) के रूप में मंजूरी दी है।
- **National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX) has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch a Mutual Fund transaction platform.**
• नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) को म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
- **The National Highways Authority of India (NHAI) received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to register the Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as an Infrastructure Investment Trust (InvIT).**





Ques : What percentage of the FY26 Budget Estimate did India's fiscal deficit reach during April–November 2025?

अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा FY26 बजट अनुमान का कितना प्रतिशत रहा?

- A) 52.5%
- B) 58.4%
- C) 60.1%
- D) 62.3%
- E) 65.0%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

- According to data released by the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit during April–November FY26 stood at ₹9.77 trillion, which is 62.3% of the Budget Estimate (BE) for the full financial year 2025–26.
- कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 में भारत का राजकोषीय घाटा ₹9.77 ट्रिलियन रहा, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 62.3% है।
- In the same period last year, the fiscal deficit was ₹8.5 trillion (52.5% of BE), indicating a higher pace of spending in the current fiscal.
- पिछले वर्ष इसी अवधि में राजकोषीय घाटा ₹8.5 ट्रिलियन (BE का 52.5%) था, जिससे चालू वित्त वर्ष में व्यय की तेज़ गति स्पष्ट होती है।
- The rise in the deficit was mainly driven by a 28% year-on-year increase in capital expenditure, even as non-tax revenues remained strong, supported by higher dividends from PSUs, public sector banks, and the RBI.
- घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण पूंजीगत व्यय में 28% की वार्षिक वृद्धि रही, हालांकि PSU, सरकारी बैंकों और RBI से अधिक लाभांश मिलने से गैर-कर राजस्व मजबूत बना रहा।
- The Centre has targeted a fiscal deficit of 4.4% of GDP for FY26.
- केंद्र सरकार ने FY26 के लिए GDP के 4.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा है।





Recent Appointment in Banking & Insurance Sector :

- **Ratan Kumar Kesh : Executive Director (ED) of Bandhan Bank**
• रतन कुमार केश : बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक (ईडी)
- **Brajesh Kumar Singh : Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank. (replaced K. Satyanarayana Raju)**
• ब्रजेश कुमार सिंह : कनारा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उन्होंने के. सत्यनारायण राजू का स्थान लिया है।)
- **Ms. Shahla Ayoub : Independent Directors in J&K Bank for Tenure 3 Years (Dec 26, 2025 – Dec 25, 2028)**
• सुश्री शाहला अयूब: जम्मू-कश्मीर बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक (26 दिसंबर 2025 - 25 दिसंबर 2028)
- **Bibhu Prasad (BP) Kanungo, former Deputy Governor of RBI : Non-Executive Chairman of the Board of IIFL Finance Limited**
• भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिभु प्रसाद (बीपी) कानूनगो : आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
- **Ashwini Kumar Tewari : Managing Director (MD) of the State Bank of India**
• अश्विनी कुमार तिवारी : भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया
- **Ravi Ranjan (Deputy MD in SBI) : Managing Director (MD) of State Bank of India (Replaced Vinay M. Tonse)**
• रवि रंजन (एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) (विनय एम. टोन्से के स्थान पर नियुक्त)
- **Ajai Kumar Shukla : Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of PNB Housing Finance**
• अजय कुमार शुक्ला: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
- **Vikram Sahu : Chief Executive Officer (CEO) of Bank of America NA (BANA) in India for a tenure of three years.**
• विक्रम साहू : भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA (BANA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तीन साल के कार्यकाल के लिए



Ques: Which group has received in-principle approval from SEBI to act as sponsor and establish a new Mutual Fund?

किस समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और नया म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

- A) Motilal Oswal Group / मोतीलाल ओसवाल समूह
- B) Edelweiss Group / एडलवाइस समूह
- C) Ashika Group / आशिका समूह
- D) JM Financial Group / जेएम फाइनेंशियल समूह
- E) IIFL Group / आईआईएफएल समूह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Ashika Group has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as a sponsor and establish Ashika Mutual Fund.
- आशिका समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और आशिका म्यूचुअल फंड की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
- This approval allows the group to form an Asset Management Company (AMC) and initiate preparations for launching mutual fund schemes, subject to final registration.
- इस मंजूरी के तहत समूह को एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) गठित करने और अंतिम पंजीकरण के अधीन म्यूचुअल फंड योजनाओं की तैयारी करने की अनुमति मिली है।
- Ashika Group was established in 1994 and operates as a comprehensive financial services platform.
- आशिका समूह की स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक वित्तीय सेवा मंच के रूप में कार्य करता है।





Ques: Who has been given additional charge as the interim Managing Director & CEO of Canara Bank?

केनरा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है?

- A) Satyanarayana Raju | सत्यनारायण राजू
- B) Brajesh Kumar Singh | ब्रजेश कुमार सिंह
- C) Hardeep Singh Ahluwalia | हरदीप सिंह अहलूवालिया
- D) Rajnish Kumar | रजनीश कुमार
- E) Ashok Chandra | अशोक चंद्र

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या:

- Canara Bank has assigned the additional charge of Managing Director & CEO to its Executive Director, Hardeep Singh Ahluwalia, with effect from January 1, 2026.
- केनरा बैंक ने 1 जनवरी 2026 से अपने कार्यकारी निदेशक हरदीप सिंह अहलूवालिया को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
- The interim appointment will remain valid for three months, or until a regular MD & CEO is appointed, or until further orders.
- यह अंतरिम नियुक्ति तीन महीनों के लिए या नियमित एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।
- The decision follows the superannuation of the incumbent MD & CEO, Satyanarayana Raju.
- यह निर्णय वर्तमान एमडी एवं सीईओ सत्यनारायण राजू के सेवानिवृत्त होने के बाद लिया गया है।
- Hardeep Singh Ahluwalia joined the banking sector in 1992 as an Agricultural Field Officer at Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of experience across diverse banking segments.
- हरदीप सिंह अहलूवालिया ने 1992 में इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में बैंकिंग करियर शुरू किया था और उन्हें विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) has recommended Brajesh Kumar Singh, currently Executive Director at Indian Bank, as the next regular MD & CEO of Canara Bank.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक के अगले नियमित एमडी एवं सीईओ के रूप में सिफारिश की है।





Ques: What major change has the Ministry of Finance introduced in the taxation of 'sin goods' such as tobacco and pan masala, effective from February 1, 2026?

1 फरवरी 2026 से तंबाकू और पान मसाला जैसे 'सिन गुड्स' के कराधान में वित्त मंत्रालय ने कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Complete removal of GST on tobacco products / तंबाकू उत्पादों पर GST को पूरी तरह समाप्त करना
B) Reduction in GST rates on cigarettes and pan masala / सिगरेट और पान मसाला पर GST दरों में कटौती
C) Replacement of GST with only excise duty / GST को केवल उत्पाद शुल्क से बदलना
D) Introduction of additional excise duty and health cess replacing GST Compensation Cess / GST क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर लागू करना
E) Uniform 18% GST on all tobacco products / सभी तंबाकू उत्पादों पर समान 18% GST लागू करना

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Finance has notified a revised tax framework for 'sin goods' such as tobacco, pan masala and related products, effective from February 1, 2026.
- वित्त मंत्रालय ने तंबाकू, पान मसाला और संबंधित 'सिन गुड्स' के लिए संशोधित कर ढांचा अधिसूचित किया है, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।
- Under the new framework, an additional excise duty and a Health and National Security Cess will replace the existing GST Compensation Cess.
- नए ढांचे के तहत मौजूदा GST क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।
- Pan masala, cigarettes and other tobacco products will continue to attract 40% GST, while biris will remain taxed at 18%.
- पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% GST जारी रहेगा, जबकि बीड़ी पर 18% GST लागू रहेगा।
- From February 1, 2026, tobacco products will be subject to an additional excise duty, while pan masala will also attract a Health and National Security Cess over and above GST.
- 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर GST के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।
- The additional excise duty rates include 91% on gutkha, 82% on chewing tobacco and jarda scented tobacco, and 33% on hookah tobacco.

|





- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरें गुटखा पर 91%, चबाने वाले तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू पर 82% तथा हुक्का तंबाकू पर 33% निर्धारित की गई हैं।
- Cigarettes will attract an excise duty ranging from ₹2,050 to ₹8,500 per 1,000 sticks, depending on length and filter type.
- सिगरेट पर लंबाई और फ़िल्टर के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ₹2,050 से ₹8,500 तक का उत्पाद शुल्क लगेगा



EXAM
Genius





Ques: Who chaired the 50th meeting of PRAGATI, marking a decade of transformative governance in India?

PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, जो परिवर्तनकारी शासन के एक दशक का प्रतीक है?

- A) Amit Shah / अमित शाह
- B) Nitin Gadkari / नितिन गडकरी
- C) Piyush Goyal / पीयूष गोयल
- D) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह
- E) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi chaired the 50th meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation), marking ten years of its role in accelerating governance and project implementation.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो इसके परिवर्तनकारी शासन में दस वर्षों को दर्शाती है।
- During the meeting, the Prime Minister reviewed five critical infrastructure projects across key sectors such as Roads, Railways, Power, Water Resources, and Coal.
- बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों से जुड़ी पाँच महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की।
- PRAGATI has been instrumental in unlocking and fast-tracking infrastructure projects that had remained stalled for decades.
- PRAGATI मंच दशकों से अटकी हुई अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।
- The Bogibeel Bridge in Assam, conceived in 1997, was completed through effective PRAGATI monitoring.
- असम का बोगीबील पुल, जिसकी परिकल्पना 1997 में की गई थी, PRAGATI की निगरानी के माध्यम से पूरा किया गया।
- The Jammu–Srinagar Rail Link, where work began in 1995, was decisively unlocked through this platform.
- जम्मू–श्रीनगर रेल लिंक परियोजना, जिसका कार्य 1995 में शुरू हुआ था, PRAGATI के माध्यम से निर्णायक रूप से आगे बढ़ी।





- Other long-pending projects unlocked include the Navi Mumbai International Airport (conceptualized in 1997), Bhilai Steel Plant Modernization (approved in 2007), and the Gadawara and LARA Thermal Power Projects (sanctioned in 2008–2009).
- अन्य लंबे समय से लंबित परियोजनाओं में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (1997), भिलाई स्टील प्लांट आधुनिकीकरण (2007) तथा गदरवाड़ा और लारा थर्मल पावर परियोजनाएँ (2008–2009) शामिल हैं।

Pro-Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI) :

- Launched : March 25, 2015
- Design & Support : Designed by PMO with help from National Informatics Centre (NIC).
- Platform Type : ICT-enabled, multi-modal platform (Data, Videoconferencing, Geo-spatial)
- The "PRAGATI Day" : Meetings are held on the fourth Wednesday of every month at 3:30 PM.
- Three-Tier System Involve : 1. PMO, 2. Union Secretaries, 3. State Chief Secretaries.
- Genesis : Based on the SWAGAT (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) platform launched by PM Modi in Gujarat in 2003.

EXAM
Genius





Ques: Under the draft Rules of the four Labour Codes, what is the mandated maximum work week?

चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम कार्य सप्ताह कितना निर्धारित किया गया है?

- A) 40 hours
- B) 45 hours
- C) 48 hours
- D) 54 hours
- E) 60 hours

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Labour Ministry has pre-published draft Rules for the four Labour Codes on its official website and invited public feedback within a 45-day window.
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व-प्रकाशित किए हैं और जनता को 45 दिनों के भीतर सुझाव देने का अवसर दिया है।
- The draft Rules comprehensively define workers, wages, types of employment, gratuity, bonus, and social security, including provisions for gig and platform workers.
- मसौदा नियमों में कर्मचारियों, वेतन, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा (गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित) को विस्तार से परिभाषित किया गया है।
- As per the draft Labour Codes Rules, a uniform 48-hour work week has been mandated across establishments.
- मसौदा श्रम संहिता नियमों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों में 48 घंटे का कार्य सप्ताह अनिवार्य किया गया है।
- Special provisions have been included for workplaces where women work night shifts, covering safety measures, consent, and transport facilities.
- रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा, सहमति और परिवहन सुविधाओं से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- The Code on Wages Rules subsume 18 existing rules, including Minimum Wages Rules and Equal Remuneration Rules, thereby simplifying the regulatory framework.
- वेतन संहिता नियमों में न्यूनतम वेतन नियम, समान पारिश्रमिक नियम सहित 18 मौजूदा नियमों को समाहित कर विनियामक ढांचे को सरल बनाया गया है।
- Minimum wages will be fixed based on the concept of a standard working-class family, which includes an earning worker, spouse, and two children, along with defined consumption and expenditure criteria.



Ques: Who was awarded the Israel Prize for Peace, Israel's highest civilian honour?

इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "इज़राइल प्राइज़ फ़ॉर पीस" किसे प्रदान किया गया?

- A) Joe Biden / जो बाइडेन
- B) Benjamin Netanyahu / बेंजामिन नेतन्याहू
- C) Volodymyr Zelenskyy / वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की
- D) Emmanuel Macron / इमैनुएल मैक्रों
- E) Donald Trump / डोनाल्ड ट्रम्प

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Israel Prize for Peace, Israel's highest civilian honour, was conferred on US President Donald Trump.
- इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "इज़राइल प्राइज़ फ़ॉर पीस" अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रदान किया गया।
- The award was presented during bilateral talks held in Florida at Donald Trump's Mar-a-Lago residence.
- यह पुरस्कार फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रम्प के मार-ए-लागो निवास पर आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रदान किया गया।
- This marks the first time the Israel Prize has been awarded to a non-Israeli citizen. It is also the first time that the Peace category of the Israel Prize has been awarded.
- यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी गैर-इज़राइली नागरिक को दिया गया है। साथ ही, यह पहला अवसर है जब इज़राइल प्राइज़ के 'शांति' वर्ग को प्रदान किया गया है।
- Notably, this recognition follows Donald Trump recently receiving the FIFA Peace Prize.
- उल्लेखनीय है कि यह सम्मान डोनाल्ड ट्रम्प को हाल ही में मिले FIFA शांति पुरस्कार के बाद प्रदान किया गया है।





Recent News Headlines Related to Awards & Winners :

- **Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, one of France's highest civilian honours : Ravi Decece**
• शेवेलियर डे ल'ऑर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक: रवि डीसी
- **'40 Under 40 Lawyer Award' 2025 : India Advocate Shubham Awasthi at 6th Edition of the BW Legal World 40 Under 40 Lawyers and Legal Influencers Awards 2025, held in New Delhi**
• '40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड' 2025 : नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यू लीगल वर्ल्ड 40 अंडर 40 लॉयर्स एंड लीगल इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड्स 2025 के छठे संस्करण में भारत के एडवोकेट शुभम अवस्थी।
- **Turner Prize : British contemporary artist Nnena Kalu**
• टर्नर पुरस्कार : ब्रिटिश समकालीन कलाकार न्नेना कालू
- **Golden Globe Horizon Award at Red Sea Film Festival : Alia Bhatt**
• रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड: आलिया भट्ट
- **Best Domestic Airline award : India's national carrier Air India**
• बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का पुरस्कार : भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया
- **Best FIFA Men's Player : France's Ousmane Dembélé**
• सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी: फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले
- **Best FIFA Women's Player : Spain's Aitana Bonmatí**
• सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी: स्पेन की एताना बोनमाटी
- **Geddes Gavel Award : Col Prateek Roy of the Indian Army**
• गेडेस गैवेल पुरस्कार: भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक रॉय
- **Oman's highest civilian honour, 'The First Class of the Order of Oman' Awarded by Sultan Haitham bin Tarik : Prime Minister Narendra Modi**
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' से सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सम्मानित किया।





Ques: Which state has become the first in India to constitute its 8th State Pay Commission ahead of the expiry of the 7th Pay Commission?

भारत में कौन-सा राज्य 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है?

- A) Assam / असम
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Assam has become the first state in India to constitute its 8th State Pay Commission, taking a proactive step ahead of the scheduled expiry of the 7th Pay Commission on January 1, 2026.
- असम 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग की निर्धारित समाप्ति से पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- The decision has drawn significant attention from state government employees and pensioners, who have been awaiting clarity on the next round of pay and pension revision.
- इस निर्णय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है, जो वेतन और पेंशन संशोधन के अगले चरण को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे।
- With this move, Assam has taken the lead over other states, even as the Union Government's 8th Pay Commission is yet to formally commence its work.
- इस कदम के साथ, असम ने अन्य राज्यों से पहले पहल की है, जबकि केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू नहीं कर पाया है।
- As per standard practice, the 8th State Pay Commission is expected to submit its recommendations within a period of around 18 months.
- सामान्य प्रथा के अनुसार, 8वां राज्य वेतन आयोग लगभग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना है।

About Assam :

- Capital : Dispur
- CM : Himanta Biswa Sarma
- Governor : Lakshman Acharya





Ques: What recent decision has NHA taken regarding the Know Your Vehicle (KYV) process for FASTags in the Car/Jeep/Van category?

कार/जीप/वैन श्रेणी के FASTag के लिए NHA ने Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को लेकर क्या निर्णय लिया है?

- A) KYV made mandatory for all existing FASTags / सभी मौजूदा FASTag के लिए KYV अनिवार्य
- B) KYV replaced with Aadhaar-based verification / KYV को आधार-आधारित सत्यापन से बदलना
- C) KYV discontinued for new FASTags except complaint-based cases / शिकायत-आधारित मामलों को छोड़कर नए FASTag के लिए KYV समाप्त
- D) KYV mandatory only for commercial vehicles / केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए KYV अनिवार्य
- E) Complete removal of vehicle verification for FASTags / FASTag के लिए वाहन सत्यापन पूरी तरह समाप्त

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Highways Authority of India (NHA) has decided to discontinue the Know Your Vehicle (KYV) process for Car/Jeep/Van category FASTags.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) ने कार/जीप/वैन श्रेणी के FASTag के लिए Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- This change will be effective from February 1, 2026, and will apply to all new FASTag issuances for cars.
- यह बदलाव 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और कारों के लिए जारी होने वाले सभी नए FASTag पर लागू होगा।
- KYV will now be required only in specific complaint-based cases such as loose FASTags, incorrect issuance, misuse, or disputes.
- अब KYV केवल कुछ शिकायत-आधारित मामलों में आवश्यक होगा, जैसे ढीले FASTag, गलत जारी करना, दुरुपयोग या विवाद।
- In the absence of any complaint, no KYV requirement will apply.
- यदि कोई शिकायत नहीं है, तो KYV की आवश्यकता नहीं होगी।
- FASTag activation will be allowed only after vehicle details are verified from the VAHAN database.
- FASTag को केवल VAHAN डेटाबेस से वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही सक्रिय किया जाएगा।
- RC-based validation will be permitted only in exceptional cases, such as when vehicle data is unavailable on VAHAN, and issuer banks will be fully accountable.





Ques: Parvati–Arga Bird Sanctuary, recently declared an Eco-Sensitive Zone, is designated as which of the following?

हाल ही में इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य किस रूप में नामित है?

- A) Biosphere Reserve / जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र
- B) Tiger Reserve / टाइगर रिज़र्व
- C) Ramsar Site / रामसर स्थल
- D) National Park / राष्ट्रीय उद्यान
- E) Community Reserve / सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government has declared the Parvati–Arga Bird Sanctuary in Uttar Pradesh as an Eco-Sensitive Zone (ESZ).
- सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित किया है।
- The sanctuary is a permanent freshwater ecosystem comprising two oxbow lakes—Parvati and Arga.
- यह अभयारण्य स्थायी मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें पार्वती और अर्गा नामक दो ऑक्सबो झीलें शामिल हैं।
- Parvati–Arga Bird Sanctuary is a Ramsar Site, underscoring its international importance as a wetland.
- पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य एक रामसर स्थल है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि महत्व को दर्शाता है।
- Spread over 1,084 hectares, it serves as a habitat for migratory birds arriving from Central Asia and Tibet.
- 1,084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आवास है।
- Eco-Sensitive Zones are notified to regulate activities around protected areas and conserve fragile ecosystems, and they may extend up to 10 km around such areas as per guidelines.
- इको-सेंसिटिव ज़ोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अधिसूचित किए जाते हैं, जो दिशानिर्देशों के अनुसार 10 किमी तक विस्तारित हो सकते हैं।





Recent News headlines related to Sports

- **Indian women's cricket achieved a major milestone as Deepti Sharma became the highest wicket-taker in Women's T20 International cricket.**
 - भारतीय महिला क्रिकेट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं।
- **Sonam Yeshey of Bhutan created history by becoming the first bowler ever to take eight wickets in a men's T20 International match.**
 - भूटान के सोनम येशे ने पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया।
- **Rashtriya Raksha University (RRU), located in Gandhinagar, Gujarat, will host eight sporting disciplines of the World Police and Fire Games (WPFNG) 2029.**
 - गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स (WPFNG) 2029 की आठ खेल विधाओं की मेजबानी करेगा।
- **Surya Charishma Tamiri from Andhra Pradesh won the Women's Singles crown at the 87th Senior National Badminton Championships held in Vijayawada.**
 - आंध्र प्रदेश की सूर्य चरिष्मा तामिरी ने विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता।
- **Virat Kohli became the fastest to score 16,000 runs in List-A cricket, achieving the milestone in just 330 innings.**
 - विराट कोहली ने मात्र 330 पारियों में 16,000 रन पूरे कर लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज़ यह उपलब्धि हासिल की।
- **Kashi (Varanasi) will host the 72nd Senior National Volleyball Championship for both men's and women's teams from January 4 to 11, 2026.**
 - काशी (वाराणसी) 4 से 11 जनवरी 2026 तक पुरुष एवं महिला वर्ग की 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
- **Indian men's hockey team vice-captain and two-time Olympic medallist Hardik Singh has been nominated for the Major Dhyan Chand Khel Ratna 2025 at the National Sports Awards.**
 - भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता हार्दिक सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है।





Ques: Who was awarded a Damehood (DBE) in King Charles III's New Year Honours List 2026?

किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में किसे डेमहुड (DBE) से सम्मानित किया गया?

- A) Meera Syal / मीरा स्याल
- B) Gurinder Chadha / गुरिंदर चड्ढा
- C) Parminder Nagra / परमिंदर नागरा
- D) Anita Rani / अनीता रानी
- E) Sanjeev Bhaskar / संजीव भास्कर

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Renowned British-Indian comedian, actress, and writer Meera Syal was awarded a Damehood (DBE) in King Charles III's New Year Honours List 2026.
- प्रसिद्ध ब्रिटिश-भारतीय कॉमेडियन, अभिनेत्री और लेखिका मीरा स्याल को किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में डेमहुड (DBE) से सम्मानित किया गया।
- Earlier, Meera Syal had been honoured with an MBE (Member of the Order of the British Empire) in 1997 and a CBE (Commander of the Order of the British Empire) in 2015.
- इससे पहले मीरा स्याल को 1997 में MBE और 2015 में CBE से सम्मानित किया जा चुका है।
- A total of 1,157 individuals were honoured in the New Year Honours List 2026.
- न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में कुल 1,157 लोगों को सम्मानित किया गया।
- Toby Roberts, aged 20 years, was the youngest recipient and was honoured with an MBE.
- 20 वर्षीय टोबी रॉबर्ट्स सबसे कम उम्र के सम्मानित व्यक्ति रहे, जिन्हें MBE प्रदान किया गया।
- John Hearn, aged 102 years, was the oldest recipient and received the BEM (British Empire Medal).
- 102 वर्षीय जॉन हर्न सबसे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति रहे, जिन्हें BEM (ब्रिटिश एम्पायर मेडल) प्रदान किया गया।





Ques: Who has been appointed as the International Event Ambassador for the 21st edition of the Tata Mumbai Marathon (TMM 2025)?

टाटा मुंबई मैराथन (TMM 2025) के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Usain Bolt (Jamaica) / उसेन बोल्ट (जमैका)
- B) Andre De Grasse (Canada) / आंद्रे डी ग्रास (कनाडा)
- C) Wayde van Niekerk (South Africa) / वेडे वान नीकरक (दक्षिण अफ्रीका)
- D) Yohan Blake (Jamaica) / योहान ब्लेक (जमैका)
- E) Fred Kerley (USA) / फ्रेड कर्ली (यूएसए)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Seven-time Olympic medallist sprinter Andre De Grasse of Canada has been appointed as the International Event Ambassador for the 21st edition of the Tata Mumbai Marathon (TMM 2025).
- कनाडा के सात बार के ओलंपिक पदक विजेता धावक आंद्रे डी ग्रास को टाटा मुंबई मैराथन (TMM 2025) के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
- The Tata Mumbai Marathon 2025 is scheduled to be held on January 18, 2026, in Mumbai, Maharashtra.
- टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा।
- The International Event Ambassador programme has been designed and curated by Procam International since the inception of the Tata Mumbai Marathon in 2004.
- अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर कार्यक्रम को 2004 में टाटा मुंबई मैराथन की शुरुआत से ही प्रोकेम इंटरनेशनल द्वारा डिज़ाइन और संचालित किया जा रहा है।





Ques: Which country has India surpassed to become the world's fourth-largest economy?

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ चुका है?

- A) Germany / जर्मनी
- B) China / चीन
- C) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
- D) Japan / जापान
- E) France / फ्रांस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India has surpassed Japan to become the world's fourth-largest economy.
- भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है।
- India's Gross Domestic Product (GDP) is estimated at USD 4.18 trillion.
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
- India is expected to overtake Germany by 2030 to become the third-largest economy globally.
- भारत के 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
- India's projected GDP by 2030 is around USD 7.3 trillion.
- 2030 तक भारत की अनुमानित GDP लगभग 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।
- Real GDP growth stood at 8.2% in Q2 of FY 2025–26, compared to 7.8% in Q1.
- वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 8.2% रही, जबकि पहली तिमाही में यह 7.8% थी।
- The growth momentum has been driven mainly by strong private consumption and robust domestic demand.
- इस तेज़ वृद्धि का मुख्य कारण मजबूत निजी उपभोग और घरेलू मांग रहा है।
- The United States remains the world's largest economy, followed by China at the second position.
- संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है।
- India continues to rank among the fastest-growing major economies in the world.





Ques: Where was the 27th edition of the FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025 held?

27वाँ FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया?

- A) Doha, Qatar / दोहा, क़तर
- B) Moscow, Russia / मॉस्को, रूस
- C) Dubai, United Arab Emirates / दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
- D) Almaty, Kazakhstan / अल्माटी, कज़ाख़स्तान
- E) Oslo, Norway / ओस्लो, नॉर्वे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The 27th edition of the FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025 was held at the Sports and Events Complex, Qatar University, Doha, Qatar.
- 27वाँ FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप 2025 क़तर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स कॉम्प्लेक्स, दोहा (क़तर) में आयोजित किया गया।
- Norwegian Grandmaster Magnus Carlsen won his sixth World Rapid Championship title in the Open category.
- नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने ओपन श्रेणी में अपना छठा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीता।
- In the Women's Rapid category, Russian Grandmaster Aleksandra Goryachkina won her maiden FIDE Women's World Rapid Championship.
- महिला रैपिड श्रेणी में रूस की ग्रैंडमास्टर एलेक्ज़ेंड्रा गोरयाचकिना ने अपना पहला FIDE महिला वर्ल्ड रैपिड खिताब जीता।
- Magnus Carlsen also clinched his ninth World Blitz Championship title in the Open category. In the Women's Blitz category, Bibisara Assaubayeva of Kazakhstan emerged as the champion.
- मैग्नस कार्लसन ने ओपन श्रेणी में अपना नौवाँ वर्ल्ड ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप खिताब भी जीता। महिला ब्लिट्ज़ श्रेणी में कज़ाख़स्तान की बिबिसारा अस्सौबायेवा विजेता बनीं।

2025 FIDE World Blitz Chess Championships:



1. Magnus Carlsen (Norway) - (Open Section), Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) - (Women's Section)
2. Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan) - (Open Section), Anna Muzychuk (Ukraine) - (Women's Section)
3. Arjun Erigaisi (India) and Fabiano Caruana (USA) - (Open Section), Zhu Jiner (China) and Eline Roebers (Netherlands) - (Women's Section)

2025 FIDE World Rapid Chess Championships:

1. Magnus Carlsen (Norway) - (Open Section), Aleksandra Goryachkina (Russia) - (Women's Section)
2. Vladislav Artemiev (Russia) - (Open Section), Zhu Jiner (China) - (Women's Section)
3. Arjun Erigaisi (India) - (Open Section), Koneru Humpy (India) - (Women's Section)

EXAM
Genius





Ques: For the first time, a specially curated animal contingent of the Remount and Veterinary Corps will feature which of the following animals?

पहली बार, रिमाउंट एवं वेटेनरी कोर की विशेष रूप से तैयार पशु टुकड़ी में निम्न में से कौन-कौन से जानवर शामिल होंगे?

- A) Horses, elephants, dolphins, and sniffer dogs / घोड़े, हाथी, डॉल्फिन और खोजी कुत्ते
B) Bactrian camels, Zanskar ponies, raptors, and Indian breed Army dogs / बैक्ट्रियन ऊँट, ज़ांस्कर टट्टू, शिकारी पक्षी और भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते
C) Arabian camels, mules, eagles, and foreign breed dogs / अरब ऊँट, खच्चर, चील और विदेशी नस्ल के कुत्ते
D) Elephants, mules, hawks, and police dogs / हाथी, खच्चर, बाज़ और पुलिस कुत्ते
E) Horses, camels, parrots, and tracker dogs / घोड़े, ऊँट, तोते और ट्रैकर कुत्ते

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- For the first time, the Remount and Veterinary Corps is showcasing a carefully curated animal contingent.
- पहली बार, रिमाउंट एवं वेटेनरी कोर द्वारा एक विशेष रूप से तैयार पशु टुकड़ी प्रदर्शित की जा रही है।
- The contingent will feature two Bactrian camels and four Zanskar ponies.
- इस टुकड़ी में दो बैक्ट्रियन ऊँट और चार ज़ांस्कर टट्टू शामिल होंगे।
- It will also include four raptors and ten Indian breed Army dogs. Additionally, six conventional military dogs already in service will be part of the contingent.
- इसके साथ चार शिकारी पक्षी (रैप्टर्स) और दस भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सेवा में पहले से कार्यरत छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी इस टुकड़ी का हिस्सा होंगे।
- The contingent highlights the diverse and specialised role of animals in the Indian Armed Forces.
- यह टुकड़ी भारतीय सशस्त्र बलों में पशुओं की विविध और विशेष भूमिका को दर्शाती है।





Ques: What new service was launched by BSNL across all telecom circles in India to improve connectivity in areas with weak cellular signals?

कमजोर मोबाइल नेटवर्क वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए BSNL ने पूरे भारत में कौन-सी नई सेवा शुरू की है?

- A) 5G Standalone Service / 5G स्टैंडअलोन सेवा
- B) Satellite Calling Service / सैटेलाइट कॉलिंग सेवा
- C) Voice over WiFi (VoWiFi) or Wi-Fi Calling / वॉयस ओवर वाई-फाई (वाई-फाई कॉलिंग)
- D) National Roaming Plus / नेशनल रोमिंग प्लस
- E) VoNR (Voice over New Radio) / वॉयस ओवर न्यू रेडियो

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) launched its Voice over WiFi (VoWiFi) service, commonly known as Wi-Fi Calling, across all telecom circles in India to mark the New Year.
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नए वर्ष के अवसर पर पूरे भारत के सभी टेलीकॉम सर्किलों में वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi), जिसे वाई-फाई कॉलिंग भी कहा जाता है, सेवा शुरू की।
- The service is specifically designed for locations with weak cellular network coverage, such as basements, high-rise buildings, and remote rural areas.
- यह सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहाँ मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है, जैसे बेसमेंट, ऊँची इमारतें और दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्र।
- VoWiFi is built on the IP Multimedia Subsystem (IMS) platform, enabling seamless call handover between Wi-Fi networks and mobile networks using Voice over LTE (VoLTE) without call drops.
- VoWiFi सेवा IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम (IMS) प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क (VoLTE) के बीच बिना कॉल कटे सहज संक्रमण सुनिश्चित करती है।

About BSNL :

- Established : 15 September 2000
- HQ : New Delhi
- CMD : A. Robert J. Ravi
- Nodal Ministry : Ministry of Communications



Ques: Which country adopted the Euro as its official currency from January 1, 2026, becoming the 21st member of the Eurozone?

1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोज़ोन का 21वां सदस्य कौन-सा देश बना?

- A) Romania / रोमानिया
- B) Croatia / क्रोएशिया
- C) Bulgaria / बुल्गारिया
- D) Hungary / हंगरी
- E) Czech Republic / चेक गणराज्य

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bulgaria adopted the Euro (EUR) as its official currency with effect from January 1, 2026, replacing the Bulgarian lev (BGN).
- बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से बल्गेरियन लेव (BGN) के स्थान पर यूरो (EUR) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है।
- The decision followed approval by the Council of the European Union on July 8, 2025, confirming that Bulgaria met all Maastricht convergence criteria.
- यह निर्णय 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद लिया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि बुल्गारिया सभी मास्ट्रिख्ट अभिसरण मानदंडों पर खरा उतरा है।
- The irrevocable conversion rate was fixed at 1 EUR = 1.95583 BGN.
- अपरिवर्तनीय रूपांतरण दर 1 यूरो = 1.95583 बल्गेरियन लेव निर्धारित की गई।
- With this move, Bulgaria became the 21st member of the Eurozone, the group of European countries using the euro as their official currency.
- इस कदम के साथ, बुल्गारिया यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बन गया, जहाँ यूरो आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है।
- Following euro adoption, the Bulgarian National Bank (BNB) joined the Eurosystem and became part of the European Central Bank (ECB) framework.
- यूरो को अपनाने के बाद, बल्गेरियन नेशनल बैंक (BNB) यूरोसिस्टम में शामिल हो गया और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) के ढांचे का हिस्सा बन गया।





Ques: What will be the name of Goa's third district, recently announced by the Chief Minister?

हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित गोवा के तीसरे ज़िले का नाम क्या होगा?

- A) Kushavati / कुशावती
- B) Zuari / जुआरी
- C) Mandovi / मांडोवी
- D) Mahadayi / महादयी
- E) Kalay / कलाय

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Goa is set to get its third district named Kushavati, marking a significant administrative reorganisation in the state.
- गोवा को कुशावती नाम का तीसरा ज़िला मिलने जा रहा है, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन को दर्शाता है।
- The announcement was made by Goa Chief Minister Pramod Sawant.
- इस घोषणा को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया।
- The new district has been named after the ancient Kushavati river that flows through parts of the region.
- नए ज़िले का नाम प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों से होकर बहती है।
- Currently, Goa has only two districts: North Goa and South Goa.
- वर्तमान में गोवा में केवल दो ज़िले हैं—उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा।

About Goa :

- Capital : Panaji
- CM : Pramod Sawant
- Governor : Ashok Gajapathi Raju





News Headlines Related to Ministry :

- **The Ministry of Defence signed defence contracts worth ₹4,666 crore in New Delhi to strengthen India's military capabilities.**
• रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ₹4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- **The Department of Telecommunications (DoT), under the Ministry of Communications, released the National Frequency Allocation Plan 2025 (NFAP-2025) for the management and allocation of radio-frequency spectrum in India.**
• संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन हेतु राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP-2025) जारी की।
- **The Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW) has notified the operational guidelines for two major shipbuilding initiatives—Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) and Shipbuilding Development Scheme (SbDS).**
• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने दो प्रमुख जहाज निर्माण पहलों—शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SbDS)—के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **According to a Ministry of Railways press release, Indian Railways has electrified 99.2% of its Broad Gauge (BG) network, bringing India close to a fully electrified railway system.**
• रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिससे भारत लगभग पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे प्रणाली के करीब पहुँच गया है।
- **The Ministry of Textiles will receive over ₹1,100 crore, which is about 22% of the total ₹6,000 crore Cotton Productivity Mission budget.**
• वस्त्र मंत्रालय को कुल ₹6,000 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन बजट का लगभग 22% यानी ₹1,100 करोड़ से अधिक प्राप्त होंगे।
- **The Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) launched the “Comprehensive Internship Policy for MYAS and its Autonomous Bodies” with an annual budget of ₹5.30 crore.**
• युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) ने ₹5.30 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ “MYAS और इसके स्वायत्त निकायों के लिए व्यापक इंटरनशिप नीति” शुरू की।





Ques: What major reform has the Department of Posts implemented regarding international mail services, effective from January 1, 2026?

1 जनवरी 2026 से डाक विभाग ने अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के संबंध में कौन-सा प्रमुख सुधार लागू किया है?

- A) Complete suspension of all international mail services / सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को पूरी तरह निलंबित करना
- B) Discontinuation of untracked and non-compliant international mail services / बिना ट्रैकिंग और गैर-अनुपालक अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को बंद करना
- C) Introduction of free international parcel services / निःशुल्क अंतरराष्ट्रीय पार्सल सेवाओं की शुरुआत
- D) Restricting international mail only to government use / अंतरराष्ट्रीय डाक को केवल सरकारी उपयोग तक सीमित करना
- E) Replacement of postal services with private couriers / डाक सेवाओं को निजी कूरियर सेवाओं से बदलना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Posts has undertaken a major rationalization of its international mail services in line with Universal Postal Union (UPU) standards.
- डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) मानकों के अनुरूप अपनी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं का व्यापक युक्तिकरण किया है।
- These reforms aim to modernize global e-commerce, improve security, and ensure 100% trackability of international shipments.
- इन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक ई-कॉमर्स को आधुनिक बनाना, सुरक्षा बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय प्रेषणों की पूर्ण ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है।
- Effective January 1, 2026, services lacking adequate tracking or modern customs compliance have been discontinued.
- 1 जनवरी 2026 से जिन सेवाओं में पर्याप्त ट्रैकिंग या आधुनिक सीमा शुल्क अनुपालन नहीं था, उन्हें बंद कर दिया गया है।
- Registered Small Packet Service has been restricted to document-only items.
- पंजीकृत स्मॉल पैकेट सेवा अब केवल दस्तावेजों तक सीमित कर दी गई है।
- Outward Small Packet Service for goods sent via Sea, SAL (Surface Air Lifted), or Air has been discontinued.





- समुद्र, SAL (Surface Air Lifted) या वायु मार्ग से भेजे जाने वाले वस्तुओं के लिए आउटवर्ड स्मॉल पैकेट सेवा बंद कर दी गई है।
- Traditional Surface and SAL outward international letter mail services have also been stopped.
- पारंपरिक सतही और SAL आधारित आउटवर्ड अंतरराष्ट्रीय पत्र डाक सेवाएँ भी बंद कर दी गई हैं।
- The move is driven by global security and customs norms, as many countries now mandate Electronic Advance Data (EAD), which untracked services cannot provide.
- यह कदम वैश्विक सुरक्षा और सीमा शुल्क मानकों के अनुरूप है, क्योंकि कई देश अब इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा (EAD) अनिवार्य कर चुके हैं, जो बिना ट्रैकिंग वाली सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकतीं।
- Certain services remain unchanged, including free Blind Literature services (except air surcharge), M-Bags governed by existing UPU norms, and registration of documents sent via Air mode.
- कुछ सेवाएँ यथावत रखी गई हैं, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्लाइंड लिटरेचर (हवाई अधिभार को छोड़कर), UPU नियमों के अंतर्गत M-बैग्स, तथा एयर मोड से भेजे गए पत्र, पोस्टकार्ड, एरोग्राम और मुद्रित पत्रों का पंजीकरण।

EXAM
Genius





Ques: What major digital milestone did India achieve in November 2025 according to PIB data?

PIB के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत ने कौन-सा प्रमुख डिजिटल मील का पत्थर हासिल किया?

- A) Crossing 500 million internet users / 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करना
- B) Achieving 100% broadband penetration / 100% ब्रॉडबैंड कवरेज प्राप्त करना
- C) Broadband subscriber base crossing 1 billion / ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब को पार करना
- D) Launch of nationwide 6G services / देशव्यापी 6G सेवाओं की शुरुआत
- E) Doubling broadband users within one year / एक वर्ष में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या दोगुनी होना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India achieved a significant digital milestone in November 2025 as its broadband subscriber base crossed 1 billion (100 crore) users for the first time.
- भारत ने नवंबर 2025 में पहली बार ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब (100 करोड़) को पार कर एक महत्वपूर्ण डिजिटल उपलब्धि हासिल की।
- According to data released by the Press Information Bureau (PIB), India had 100.37 crore broadband subscribers by the end of November 2025.
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के अंत तक भारत में 100.37 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे।
- This marks the first instance of the country crossing the 1 billion subscriber threshold.
- यह देश द्वारा पहली बार 1 अरब उपभोक्ता सीमा को पार करने की घटना है।
- In November 2015, broadband subscribers numbered 131.49 million (13.15 crore).
- नवंबर 2015 में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 131.49 मिलियन (13.15 करोड़) थी।
- By November 2025, the subscriber base had expanded to 100.37 crore, representing more than a six-fold increase in ten years.
- नवंबर 2025 तक यह संख्या बढ़कर 100.37 करोड़ हो गई, जो एक दशक में छह गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाती है।





Ques: Which ministry unveiled a new institutional identity with a revamped logo and a first-of-its-kind mascot themed “Data for Development”?

“डेटा फॉर डेवलपमेंट” थीम के तहत नया संस्थागत पहचान (रीवैण्ड लोगो और प्रथम-प्रकार के मैस्कॉट) किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) Ministry of Electronics & IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- C) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- D) Ministry of Information & Broadcasting / सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) unveiled its new institutional identity, featuring a redesigned logo and a first-of-its-kind mascot.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नया संस्थागत पहचान प्रस्तुत किया, जिसमें पुनः डिज़ाइन किया गया लोगो और एक अनोखा मैस्कॉट शामिल है।
- The initiative is themed “Data for Development” and aims to humanize official statistics while bridging the gap between complex data and the general public.
- यह पहल “डेटा फॉर डेवलपमेंट” थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक आँकड़ों को मानवीय बनाना और जटिल डेटा व आम नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है।
- The Ashoka Chakra in the logo symbolizes truth, transparency, and good governance in data collection.
- लोगो में अशोक चक्र डेटा संग्रह में सत्य, पारदर्शिता और सुशासन के मूल्यों का प्रतीक है।
- The Rupee symbol (₹) placed at the center highlights the importance of statistics in economic planning, national growth, and policymaking.
- केंद्र में स्थित रुपये का प्रतीक (₹) आर्थिक योजना, राष्ट्रीय विकास और नीति निर्माण में सांख्यिकी की अहम भूमिका को दर्शाता है।
- An upward growth bar represents the nation’s progress and reflects how reliable data forms the foundation of sustainable economic growth.
- ऊपर की ओर बढ़ती ग्रोथ बार देश की प्रगति और सतत आर्थिक विकास में विश्वसनीय डेटा की भूमिका को दर्शाती है।





News Headlines Related to Ministry :

- **The Ministry of Defence signed defence contracts worth ₹4,666 crore in New Delhi to strengthen India's military capabilities.**
• रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ₹4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- **The Department of Telecommunications (DoT), under the Ministry of Communications, released the National Frequency Allocation Plan 2025 (NFAP-2025) for the management and allocation of radio-frequency spectrum in India.**
• संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन हेतु राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP-2025) जारी की।
- **The Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW) has notified the operational guidelines for two major shipbuilding initiatives—Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) and Shipbuilding Development Scheme (SbDS).**
• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने दो प्रमुख जहाज निर्माण पहलों—शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SbDS)—के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **According to a Ministry of Railways press release, Indian Railways has electrified 99.2% of its Broad Gauge (BG) network, bringing India close to a fully electrified railway system.**
• रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिससे भारत लगभग पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे प्रणाली के करीब पहुँच गया है।
- **The Ministry of Textiles will receive over ₹1,100 crore, which is about 22% of the total ₹6,000 crore Cotton Productivity Mission budget.**
• वस्त्र मंत्रालय को कुल ₹6,000 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन बजट का लगभग 22% यानी ₹1,100 करोड़ से अधिक प्राप्त होंगे।
- **The Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) launched the “Comprehensive Internship Policy for MYAS and its Autonomous Bodies” with an annual budget of ₹5.30 crore.**
• युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) ने ₹5.30 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ “MYAS और इसके स्वायत्त निकायों के लिए व्यापक इंटरनशिप नीति” शुरू की।

